ब्रहस्पतिवार, 2 मार्च, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा रन चेज अब न्यूजीलैंड के नाम

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

मुंबई समारोह में सुनील पाल के साथ हुआ अपमान

Page-05

तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते संघर्ष से तेज हुई है। ट्रंप ने नाटो पर भी विवादित बयान दिए। तेल मार्गों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर संकट गहरा गया, कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत बढ़ी।

ऊर्जा संकट में भारत बना दक्षिण एशिया का भरोसेमंद केंद्र

- **दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका बनी निर्णायक**
- **मोदी की रणनीति और कूटनीति का प्रभाव**

दक्षिण एशिया की राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा में हालिया मोड़ किसी भूचाल से कम नहीं है। कुछ महीने पहले तक भारत को घेरने की साजिश रचने वाले पड़ोसी देश अब उसी भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। ईरान युद्ध से उपजा ऊर्जा संकट पूरे क्षेत्र की असलियत उजागर कर रहा है। जो देश कभी "इंडिया आउट" का नारा लगा रहे थे, आज वही भारत से तेल और गैस की मदद मांग रहे हैं। यह केवल कूटनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का निर्णायक क्षण है। होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कच्चे तेल का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा एशियाई देशों के लिए है। युद्ध ने इस जीवनरेखा को झकझोर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देश ऊर्जा निर्भरता के संकट में फंस गए हैं। भारत भी आयात पर निर्भर है, लेकिन उसकी रणनीतिक तैयारी और संतुलित कूटनीति ने उसे मजबूती दी है। ईरान ने भारत को मित्र मानते हुए तेल और गैस की आपूर्ति के रास्ते खोले, जिससे देश को राहत मिली।भारत ने केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं की, बल्कि पड़ोसी देशों की मदद का बीड़ा उठाया। बांग्लादेश ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा शिकार बना। देश अपनी जरूरत का 95 प्रतिशत तेल और 30 प्रतिशत गैस आयात करता है। बिजली कटौती, उद्योगों का ठप होना और विश्वविद्यालयों का बंद होना इसका प्रमाण हैं। भारत ने तुरंत असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पाइपलाइन के जरिए डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति शुरू की।मालदीव और श्रीलंका की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण रही। एक साल पहले तक भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जु अब भारत को "विश्वसनीय साथी" मान रहे हैं। श्रीलंका, जो ऊर्जा जरूरत का 60 प्रतिशत आयात करता है, भी संकट में फंस गया था। भारत ने यहां भी तुरंत ईंधन की आपूर्ति की और राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से आभार जताया।नेपाल में भी भारत की मदद लगातार जारी रही। हिमालयी भूगोल और सीमित संसाधनों के कारण नेपाल पूरी तरह आयात पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीति और निर्णायक नेतृत्व इस सफलता के केंद्र में हैं। पड़ोसी देश अब भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मान रहे हैं। यह बदलाव केवल कूटनीति का नतीजा नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, सहयोग और रणनीतिक निर्णय का परिणाम है। आज भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि संकट में भरोसे का प्रतीक बन चुका है।

ट्रंप को करारा संदेश: ब्रिटेन अमेरिका के युद्ध में नहीं करेगा भागीदारी

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को घोषणा की कि उनका देश होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में कुल 35 देशों ने हिस्सा लेने और इस रणनीतिक तेल मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर सहमति जताई है। यह कदम इस क्षेत्र में हाल ही में बढ़े तनाव और ईरान, इज़राइल तथा खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच जारी संघर्ष के मद्देनजर उठाया गया है।स्टारमर ने कहा कि सम्मेलन का नेतृत्व ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर करेंगी, जबकि सैन्य योजनाकार युद्ध के बाद क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और संभावित संकटों से निपटने की रणनीति तैयार करने में सक्रिय रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कूटनीतिक प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि "सैन्य शक्ति और कूटनीतिक प्रयासों का संयुक्त मोर्चा" ही क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित कर सकता है।इस दौरान एक संवाददाता ने उनसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में नाटो से अमेरिका को अलग करने के संभावित बयान पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। इस पर स्टारमर ने कहा कि वे किसी भी दबाव, राजनीतिक विवाद या शोर-शराबे के बावजूद केवल ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रिटेन की नीतियां किसी भी बाहरी प्रभाव

केरल में राजनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को परवूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों गठबंधन दशकों से केरल के मेहनती और ईमानदार लोगों को धोखा देते आए हैं।राजनाथ सिंह ने कहा कि केरल की जनता एलडीएफ या यूडीएफ को चुनने के लिए वोट नहीं देती, बल्कि एक को सत्ता से हटाने के लिए मतदान करती है, जिससे दूसरा गठबंधन स्वतः सत्ता में आ जाता है। उन्होंने दोनों गठबंधनों पर समाज को बांटने और राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा, "एलडीएफ का मतलब लूट, विभाजन और विफलता है, जबकि यूडीएफ अविश्वास, बेईमानी और धोखाधड़ी का प्रतीक है।" सिंह ने आगे कहा कि दोनों गठबंधनों में 'एफ' का मतलब "भ्रष्टाचार का मोर्चा" है।यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है।

पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ के चाय बागान का दौरा किया

श्रमिकों का योगदान विश्व स्तर पर सराहनीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के डिब्रूगढ़ में स्थित एक चाय बागान का दौरा किया और वहां काम कर रहे श्रमिकों से बातचीत कर उनकी मेहनत और योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि "चाय असम की आत्मा है और यहां की चाय विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखती है।" पीएम मोदी ने बागान की महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनकी कड़ी मेहनत की तारीफ की। उन्होंने बताया कि चाय पत्तियां तोड़ने के बाद श्रमिकों ने उन्हें अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने एक सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री ने अपने बचपन की यादें साझा करते हुए कहा कि वे गुजरात में रेलवे स्टेशन पर अपने पिता को चाय बेचने में मदद किया करते थे और चाय के प्रति उनका व्यक्तिगत जुड़ाव उस समय से है। असम विश्व के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है, जिसमें डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और जोरहाट प्रमुख जिले हैं। यह उद्योग न केवल लाखों श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि भारत के चाय निर्यात और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि यह चुनाव विकसित भारत की परिकल्पना को आकार देगा।

ओरेकल की बड़ी छंटनी: 30,000 कर्मचारियों पर गिरी गाज

क्लाउड और सॉफ्टवेयर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल ने अपने वैश्विक कार्यबल से करीब 30,000 कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कंपनी ने 15 वर्षों का सबसे अधिक तिमाही राजस्व 17.2 बिलियन डॉलर दर्ज किया है।रिपोर्ट्स के अनुसार, इस छंटनी का सबसे अधिक असर भारत और मैक्सिको जैसे बाजारों पर पड़ा है। भारत में ओरेकल के लगभग 30,000 कर्मचारियों में से करीब 12,000 कर्मचारियों की नौकरी जाने की आशंका जताई जा रही है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह छंटनी कंपनी की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह पारंपरिक सॉफ्टवेयर सेवाओं से हटकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बताया जा रहा है कि ओरेकल ने अगले पांच वर्षों में एआई डेटा सेंटर विकसित करने के लिए लगभग 156 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें ओपनएआई जैसे प्रमुख ग्राहक शामिल हैं। इस बड़े निवेश के चलते कंपनी के खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई है। दो साल पहले जहां इसका वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च 6.9 बिलियन डॉलर था, वहीं अब यह बढ़कर करीब 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसे में लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है।इसके अलावा ओरेकल पर 108 बिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज भी है, जिससे कंपनी पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है। अनुमान है कि इस छंटनी से कंपनी को 8 से 10 बिलियन डॉलर तक की बचत हो सकती है, जिसे एआई और डेटा सेंटर विस्तार में लगाया जाएगा।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2 - 3)	फुल पेज (कवर 4 - अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

जनगणना 2027: घरों की सूची अभियान 1 अप्रैल से शुरू

स्मार्टफोन और ऑनलाइन पोर्टल से होगी डेटा संग्रहण

जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के रूप में शुरू होगा। पहली बार स्मार्टफोन और ऑनलाइन पोर्टल से डेटा संग्रहण होगा। दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से जनसंख्या गणना के लिए शुरू होगा, जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

देश में 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना का अभ्यास आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस बार जनगणना का पहला चरण – हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना – 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी निर्धारित 30-दिन की अवधि में यह अभियान संचालित करेगा। अगले वर्ष 1 मार्च 2027 से जनसंख्या गणना का दूसरा चरण शुरू होगा।जनगणना आयुक्त मृत्युञ्जय कुमार नारायण ने बताया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) में प्रत्येक संरचना, घर और परिवार की सूची तैयार की जाएगी। इसमें घर की संरचना, निर्माण सामग्री, उपयोग का उद्देश्य, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या, भवन के स्वामित्व का विवरण और कमरों की संख्या जैसे विवरण एकत्र किए जाएंगे। यह चरण भविष्य में जनसंख्या गणना (पीई) के लिए डेटा-आधारित आधार तैयार करेगा। कुल 33 प्रश्नों के माध्यम से परिवारों, जीवन स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। विशेष रूप से इस बार पहली बार जनगणना कर्मी स्मार्टफोन का उपयोग करके मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा एकत्र और जमा करेंगे। इससे पारंपरिक कागज आधारित प्रणाली की जगह आधुनिक तकनीक लेगी। इसके अलावा, नागरिकों को स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन डेटा जमा करने का विकल्प मिलेगा। यह पोर्टल हिंदी और अंग्रेजी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। अधिकारियों ने बताया कि उत्तरदाता अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं, अपने परिवार का विवरण भर सकते हैं और एक अद्वितीय स्व-गणना आईडी प्राप्त करेंगे, जिसे गणनाकर्ता के दौरे के दौरान साझा किया जाएगा।विशेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यक्रम का समय-सारणी इस प्रकार है: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में 16 अप्रैल से 15 मई तक घरों की सूची तैयार की जाएगी, जबकि स्व-गणना 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में 1 मई से 30 मई तक घरों की सूची तैयार होगी, जबकि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्व-गणना पूरी की जाएगी।जनसंख्या गणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा। हिम-आच्छादित क्षेत्रों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह कार्य सितंबर 2026 से पहले ही शुरू हो जाएगा। इन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। शेष पूरे देश में जनसंख्या गणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे तय की गई है। आयोग ने यह भी बताया कि दूसरे चरण के दौरान जातियों की गणना भी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन स्व-गणना के माध्यम से डेटा संग्रहण में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी। यह अभियान देश में सामाजिक-आर्थिक, शहरी और ग्रामीण विकास की योजना बनाने में महत्वपूर्ण आधार का काम करेगा।इस तरह, जनगणना 2027 देश की आबादी, जीवन स्तर और बुनियादी ढांचे की वास्तविक स्थिति का नवीनतम आंकड़ा प्रस्तुत करेगी, जिससे नीति निर्धारण और योजना निर्माण और अधिक सटीक और प्रभावी बन सकेगा।

एटीएफ और रसोई गैस की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

ईरान युद्ध भले ही भारत से बहुत दूर हो रहा हो लेकिन उसका असर अब यहां सबकी जेब पर तेजी से पड़ने लगा है। हम आपको बता दें कि वैश्विक तेल कीमतों में उछाल के कारण विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत में आज भारी वृद्धि की गयी है इसके साथ ही व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में भी एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। हम आपको याद दिला दें कि विमानन ईंधन की कीमतें दो दशक पहले नियंत्रण मुक्त कर दी गई थीं और तब से इन्हें अंतरराष्ट्रीय मानक कीमतों के अनुरूप तय किया जाता है। वैसे यह पहला मौका है जब एटीएफ की कीमत दो लाख रुपये प्रति किलोलीटर के स्तर को पार कर गई है। हम आपको बता दें कि ईंधन की कीमतों में यह उछाल विमानन कंपनियों पर अतिरिक्त दबाव डालेगा क्योंकि कुल परिचालन लागत में ईंधन की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत रहती है। साथ ही पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कई हवाई मार्ग बंद होने से विमानों को लंबे रास्तों से उड़ान भरनी पड़ रही है जिससे ईंधन की खपत भी बढ़ रही है। इसी के साथ 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर (होटल-रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाला) की कीमत भी 195.50 रुपये बढ़ा दी गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 2,078.50 रुपये हो गई है। देखा जाये तो पश्चिम एशिया में भड़कती जंग, हार्मुज जलडमरूमध्य का बंद होना और वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी उथल पुथल ने देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा वार किया है। केंद्र सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए हवाई ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में संभावित भारी बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद संकट की आंच अब हर क्षेत्र तक पहुंचती दिख रही है।

मोजतबा खामेनेई की सार्वजनिक चुप्पी बढ़ाती रहस्य की परतें

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के पुत्र मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके ठिकाने और हालचाल को लेकर वैश्विक स्तर पर अटकलें जारी हैं।रूसी मीडिया आउटलेट RTIV के अनुसार, मॉस्को में ईरान के राजदूत ने कहा कि मोजतबा देश में मौजूद हैं, लेकिन "समझने योग्य कारणों" से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे। यह बयान उनके स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है। 28 फरवरी को अमेरिका-इज़राइल के हमले में अपने पिता की मृत्यु के बाद मोजतबा ने ईरान में सर्वोच्च नेता का पद संभाला था। तब से वे एक बार भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। उनके नाम से अब तक जारी किए गए सभी बयान लिखित रूप में रहे हैं और सरकारी टेलीविजन पर प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें 12 मार्च को उनका पहला संबोधन और 20 मार्च का नवरोज संदेश शामिल है। हाल ही में

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोजतबा की स्थिति को लेकर अनिश्चितता बढ़ाते हुए कहा कि ईरान के नए नेता "मृत या गंभीर स्थिति में हो सकते हैं।" वाशिंगटन ने भी संकेत दिया कि मोजतबा घायल हो सकते हैं, हालांकि इसका कोई आधिकारिक पुष्टिकरण नहीं हुआ है। इसके बावजूद, ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि मोजतबा ने एक संदेश जारी कर इराक के लोगों और धार्मिक नेतृत्व को "आक्रामकता का सामना करने में तेहरान के समर्थन" के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया कि संदेश कैसे या कहाँ से भेजा गया।

नेतन्याहू का ईरान पर वार

इज़रायल चुपचाप बना रहा नए क्षेत्रीय गठबंधन

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि इज़रायल ईरान के खतरे का सामना करने के लिए चुपचाप एक नए क्षेत्रीय गठबंधन का निर्माण कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि यह गठबंधन मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण देशों के साथ इज़रायल के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने शामिल देशों के नाम तो नहीं लिए, लेकिन आश्वासन दिया कि जल्द ही इस गठबंधन और समझौतों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।नेतन्याहू ने इस पहल को अपने युद्धक्षेत्र में मिली बड़ी जीत का हिस्सा बताते हुए कहा कि हाल के अभियानों ने ईरान की परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इज़रायल ने ईरान द्वारा परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों के तत्काल खतरे को खत्म कर दिया और ईरान की औद्योगिक क्षमता को भी प्रभावित किया है, जिससे ऐसे हथियारों के उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित हुआ।प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव अब पहले जितना व्यापक नहीं रहा। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिज़्बुल्लाह अब इज़रायल के लिए रणनीतिक खतरा नहीं है। नेतन्याहू ने तेहरान में दीर्घकालिक परिवर्तन की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि "देर-सवेर, ईरानी शासन का पतन होगा। यह गठबंधन ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सऊदी अरब की बड़ी कार्रवाई

हवा में दो ड्रोन मार गिराए

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आईं, जिनसे क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ समय के लिए उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा, जबकि ईरान और सऊदी अरब से भी हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (DXB) के आसपास सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया गया। हालांकि, कुछ विमान अपनी निर्धारित यात्रा जारी रखने में सफल रहे। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटरादार24 के अनुसार, आखिरी लैंडिंग लगभग एक घंटे पहले दर्ज की गई थी, जिससे संकेत मिलता है कि स्थिति अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थी। अधिकारियों ने अभी तक इस व्यवधान के पीछे के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच, तेहरान से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां स्थित पूर्व अमेरिकी दूतावास भवन को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। ईरानी

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बुधवार तड़के हुए इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दूतावास परिसर के पूर्वी हिस्से में, तालेघानी और दक्षिण मोफत्तेह सड़कों के चौराहे के पास नुकसान देखा गया है। हालांकि, इस घटना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही हमले की प्रकृति या क्षति की सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। वहीं, सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने पिछले कुछ घंटों में दो ड्रोन हमलों को नाकाम करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया। सऊदी अरब, जो अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी है, हाल के दिनों में ईरान समर्थित हमलों का लगातार निशाना बनता रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों में दो दर्जन से अधिक अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

संपादक की कलम से

भारत अब विद्युत वाहन (EV) क्रांति की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की फास्टैग, FAME-II और ग्रीन मोबिलिटी योजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधार और वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। यह सिर्फ परिवहन का बदलाव नहीं, बल्कि प्रदूषण कम करने और देश को ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने की पहल है। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे बड़े शहरों में ई-स्कूटर्स और ई-कारों का चलन बढ़ा है। मुख्य कारण हैं: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, सरकारी सब्सिडी और बढ़ती पर्यावरण जागरूकता। साथ ही, निजी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया है, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिली है।सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश में 50 प्रतिशत नए वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाया जाए। इसके लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क और बैटरी उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है। घरेलू बैटरी उद्योग में निवेश से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और भारत का निर्माण क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत होगा। हालांकि, चुनौतियां भी हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत अभी भी पारंपरिक वाहनों से अधिक है। इसके अलावा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में समान रूप से विकसित नहीं है। बैटरी रीसाइक्लिंग और प्रदूषण नियंत्रण भी बड़े मुद्दे हैं। निजी और सरकारी क्षेत्र को मिलकर इन बाधाओं को दूर करना होगा।विद्युत वाहनों के लाभ स्पष्ट हैं। यह न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में ध्वनि और वायु प्रदूषण में भी कमी लाता है। इसके अलावा, पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ता है।इस क्रांति को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि नागरिकों में जागरूकता बढ़े और सरकार टिकाऊ योजनाओं के माध्यम से उत्पादन, सब्सिडी और चार्जिंग सुविधाओं का समन्वय बनाए। यदि यह कदम समय पर उठाए गए, तो भारत न केवल स्वच्छ और हरित परिवहन में वैश्विक उदाहरण बन सकता है, बल्कि रोजगार और तकनीकी नवाचार में भी अग्रणी देश बन जाएगा।विद्युत वाहन सिर्फ तकनीक का परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह भारत के हरित और सतत भविष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं।

असम में विकास की गति तेज

भाजपा की हैट्रिक तय: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में रैली के दौरान विकास कार्यों को गिनाते हुए भाजपा की हैट्रिक का भरोसा जताया। उन्होंने महिलाओं, किसानों और उद्योगों के लिए योजनाओं का उल्लेख किया तथा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असम तेजी से विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के गोगामुख में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य ने पिछले दस वर्षों में अभूतपूर्व विकास देखा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सत्ता में लाएगी। उन्होंने जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ और युवाओं के उत्साह को विकास और स्थिरता के प्रति समर्थन का स्पष्ट संकेत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी चुनाव केवल सरकार बनाने का नहीं, बल्कि "विकसित भारत" के निर्माण की दिशा तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर "हैट्रिक" दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि असम में चुनाव की घोषणा के बाद यह उनकी पहली जनसभा है और यहां उपस्थित जनसमूह यह साबित करता है कि जनता का समर्थन भाजपा के साथ मजबूती से बना हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में राज्य में सुशासन और सेवा का नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि असम का विकास अब पूरे भारत के विकास से जुड़ चुका है और यह चुनाव "विकसित असम से विकसित भारत" बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है।प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि "लखपति दीदी" अभियान के तहत असम की करीब तीन लाख महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अब इस संख्या को बढ़ाकर 40 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम बताया।सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने असम की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ-साथ आदिवासी समाज और छठी अनुसूची क्षेत्रों की परंपराओं की रक्षा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के लगभग 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।प्रधानमंत्री ने बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तटबंधों के निर्माण पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। अपने भाषण में उन्होंने असम के औद्योगिक विकास पर भी प्रकाश डाला और कहा कि राज्य जल्द ही सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में असम केवल चाय के लिए ही नहीं, बल्कि चिप निर्माण के लिए भी दुनिया भर में जाना जाएगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक शासन किया, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि आज असम में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में कहा कि भाजपा-एनडीए सरकार राज्य की अस्मिता, सुरक्षा और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनता का आशीर्वाद मिलने पर यह विकास यात्रा और तेज होगी।

DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली से किया चुनावी अभियान का आगाज

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले DMK प्रमुख और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को तिरुचिरापल्ली से अपने चुनावी अभियान की जोरदार शुरुआत की। 'करुणानिधि का बेटा हूँ' के उद्घोष के साथ स्टालिन ने किसानों और महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं कीं और राज्य में अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर किया।स्टालिन ने कहा कि उनकी सत्ता में वापसी पर राज्य के 20 लाख किसानों को मुफ्त पंपसेट प्रदान किए जाएंगे और धान की खरीद 3,500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर की जाएगी। उन्होंने तिरुचि क्षेत्र में एक बड़ी लाइब्रेरी, TIDEL पार्क और ओलंपिक अकादमी शुरू करने का भी वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरुचिरापल्ली को राजधानी चेन्नई के बराबर विकसित किया जा रहा है।उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि AIADMK, जो पिछले 10 साल तक सत्ता में रही, ने तमिलनाडु को पतन की ओर धकेल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP ने तमिलनाडु को कोई फंड नहीं दिया और एडप्पादी पलानीस्वामी सरकार केवल रिश्तेदारों को ठेके देने तक सीमित रही।स्टालिन ने DMK की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए हर महीने 1,000 रुपये, पौष्टिक नाश्ता योजना और 'नान मुधलवन' जैसी कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में तिरुचिरापल्ली के लिए 26,000 करोड़ रुपये की योजनाएँ लागू की गईं।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में कोई जातिगत या सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती, जबकि UP और मणिपुर जैसे राज्यों में हिंसा लगातार जारी है। उन्होंने दावा किया कि DMK शासन में शांतिपूर्ण माहौल और प्रभावी प्रशासन के कारण तमिलनाडु में निवेश लगातार बढ़ रहा है।स्टालिन ने अंत में जनता से आह्वान किया कि वे DMK को वोट दें ताकि राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाएं लगातार जारी रहें। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी घोषणाएं आने वाले दिनों में पूरी की जाएँगी और राज्य की जनता का जीवन स्तर और बेहतर होगा।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने

बीजू पटनायक पर विवादित बयान के लिए माफी मांगी

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के खिलाफ अपनी हालिया टिप्पणी को लेकर विवाद के बाद बिना शर्त माफी जारी की। X (पूर्व ट्विटर) पर साझा किए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते समय उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके विचार नेहरू-गांधी परिवार और भारत के अग्रणी नेताओं के प्रति थे, न कि बीजू पटनायक के खिलाफ।दुबे ने लिखा, "बीजू बाबू हमेशा से हमारे लिए एक महान राजनेता रहे हैं और रहेंगे। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके नेहरू के प्रति विचार को पटनायक के संदर्भ में गलत समझा गया।यह विवाद 27 मार्च को निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए बयानों से शुरू हुआ था। उस समय दुबे ने 1960 के दशक में भारत की विदेश और रक्षा नीतियों पर कई आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि 1962 के भारत-चीन युद्ध से पहले और बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अमेरिका और सीआईए के साथ संबंध था। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पटनायक अमेरिकी सरकार, सीआईए और नेहरू के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे और उन्हें रक्षा संबंधी संवेदनशील जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।दुबे ने यह भी कहा कि अमेरिका ने तिब्बत में अपने सैनिक और सीआईए एजेंट भेजे, यह जानते हुए कि चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेगा। उन्होंने दावा किया कि दलाई लामा और उनके भाई अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में थे, और नेहरू ने 1962 का पूरा चीन युद्ध अमेरिकी सहायता और एजेंटों के सहयोग से लड़ा।इस बयान के बाद

भाजपा ने सांसद की टिप्पणी से खुद को अलग किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजयंत जय पांडा ने कहा कि दिवंगत नेता बीजू पटनायक कद्दावर शख्सियत थे और उनकी देशभक्ति पर किसी भी प्रकार का संदेह अस्वीकार्य है।पार्टी के भीतर और सार्वजनिक स्तर पर उठी आलोचनाओं के बाद निशिकांत दुबे ने स्पष्ट किया कि उनका बयान व्यक्तिगत विचार था और किसी को ठेस पहुंची हो तो वह माफी मांगते हैं।

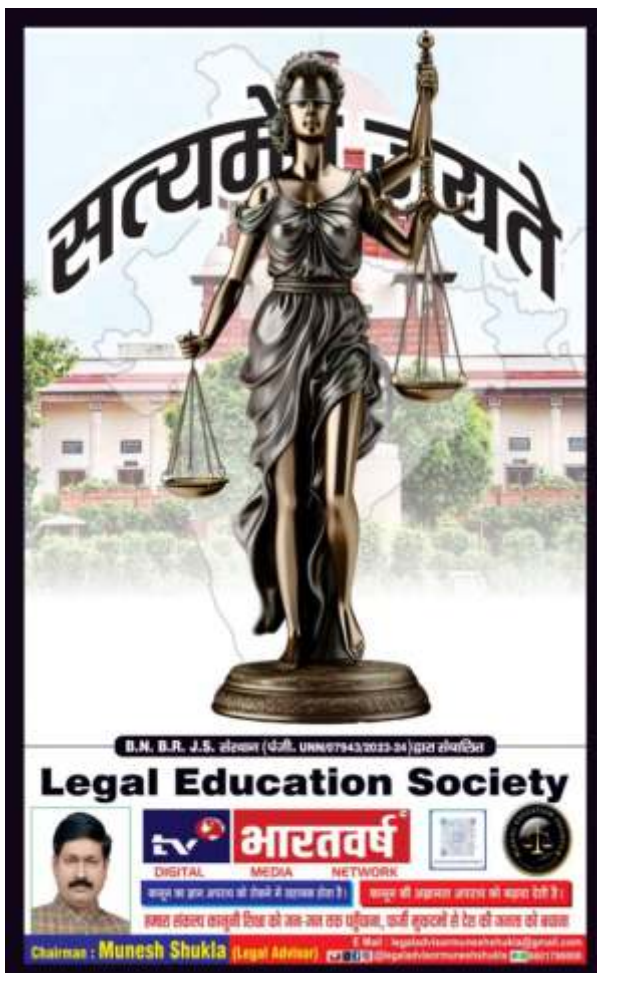

फ्री लिमिट पार करते ही लगेगा 23 रुपये का जुर्माना और टैक्स

बैंकिंग नियमों में बदलाव के चलते अब एटीएम से बार-बार नकदी निकालना महंगा पड़ सकता है। देशभर के प्राइवेट और सरकारी बैंक 1 अप्रैल 2026 से नए एटीएम नियम लागू कर चुके हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों को एटीएम ट्रांजेक्शन के प्रति सजग करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के ग्राहक अब एटीएम से महीने में केवल 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यदि ग्राहक अन्य बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो मेट्रो शहरों में फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 है। अब एचडीएफसी ग्राहक UPI के माध्यम से भी एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। हालांकि, इस तरह की निकासी भी फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट में गिनी जाएगी। फ्री लिमिट पार होने पर प्रति ट्रांजेक्शन 23 रुपये शुल्क देना होगा। इस शुल्क पर टैक्स भी लागू होगा।देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने भी एटीएम से नकदी निकालने के नियमों में बदलाव किए हैं। RuPay NCMC प्लेटिनम डोमेस्टिक/इंटरनेशनल, RuPay वुमेन पावर प्लेटिनम, RuPay पीएनबी पलाश, रिसायकल्ड पीवीसी, RuPay बिजनेस प्लेटिनम, मास्टर कार्ड प्लेटिनम, VISA गोल्ड और पीएनबी मास्टरकार्ड प्लेटिनम राइज कार्ड धारकों की एटीएम कैश निकासी की प्रतिदिन सीमा घटाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। वहीं RuPay सेलेक्ट डेबिट कार्ड, PNB RuPay सेलेक्ट नियो, PNB RuPay सेलेक्ट एक्सल, VISA सिग्नेचर और मास्टरकार्ड बिजनेस कार्ड के लिए यह सीमा 1,50,000 रुपये से घटाकर 75,000 रुपये कर दी गई है।बंधन बैंक ने भी एटीएम नियमों में संशोधन किया है। बैंक के अनुसार, बंधन बैंक के ग्राहकों को महीने में 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे, जबकि नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की कोई सीमा नहीं है। अन्य बैंक के एटीएम पर ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 है। यदि फ्री ट्रांजेक्शन की सीमा पार होती है, तो प्रति फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 23 रुपये और प्रति नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 10 रुपये शुल्क लगेगा।यदि किसी ग्राहक के बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और एटीएम ट्रांजेक्शन अस्वीकृत होता है, तो उसे 25 रुपये का जुर्माना देना होगा।बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम ग्राहकों को डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन बैंकिंग का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे नकदी का इस्तेमाल कम होगा और बैंकिंग लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। वित्तीय शिक्षा के तहत छात्रों और आम लोगों को यह समझना जरूरी है कि एटीएम से बार-बार कैश निकालना केवल अर्थव्यवस्था पर दबाव नहीं डालता, बल्कि व्यक्तिगत खर्च को भी बढ़ाता है। आवश्यकता अनुसार ही एटीएम से पैसे निकाले जाएँ और डिजिटल भुगतान विकल्पों का अधिक उपयोग करें। नए नियम के साथ, बैंकिंग व्यवहार में सावधानी, योजना और डिजिटल उपयोगिता की अहमियत और बढ़ गई है।

"टूर्नामेंट कम, ट्रेनिंग ज्यादा: विश्व शतरंज चैंपियन की नई रणनीति"

मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने इस सत्र में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपने टूर्नामेंट कार्यक्रम को कम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने 2026 में केवल दो ग्रैंड शतरंज टूर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का विकल्प चुना है, ताकि वह अपने खिताब की रक्षा के लिए ट्रेनिंग और तैयारी को प्राथमिकता दे सकें।गुकेश का हालिया प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। नवंबर 2025 में भारत में आयोजित शतरंज विश्व कप में शीर्ष वरीय होने के बावजूद वह शुरुआती राउंड में ही बाहर हो गए थे। इसके बाद दिसंबर में विश्व रैपिड और ब्लिट्ज़ चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन कमजोर रहा। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में टाई-ब्रेक के बाद वह 10वें स्थान पर रहे, जबकि हाल ही में समाप्त हुए प्राग शतरंज महोत्सव में उन्हें नौवां स्थान मिला।डी गुकेश ने 'एक्स' पर लिखा, "पिछले कुछ टूर्नामेंट में मेरा प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। यह केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जो मेरा समर्थन करते हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म हासिल करने के लिए मेरी टीम और मैंने यह फैसला किया है कि अगले कुछ महीनों तक मुझे थोड़ी कम तीव्रता के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि लंबी अवधि के टूर्नामेंट में हिस्सा न लेकर उन्हें प्रशिक्षण के लिए अधिक समय मिलेगा।गुकेश ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अब 2024 में सिंगापुर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर जीते गए विश्व खिताब की रक्षा करना है। उनके पूरे ग्रैंड शतरंज टूर में नहीं खेलने के निर्णय के बाद, आयोजकों ने उनकी जगह मौजूदा विश्व कप चैंपियन जावोखिर सिंदारोव को शामिल किया है।गुकेश अब सात से 12 अप्रैल तक स्पेन में आयोजित 26,000 यूरो के मास्टर्स चेस मेनोरका में भाग लेंगे। इस निर्णय से यह संकेत मिलता है कि विश्व चैंपियन अपनी लंबी अवधि की तैयारी और रणनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ICC WT20 रैंकिंग में भूचाल
जॉर्जिया वॉल ने नंबर-1 बल्लेबाज का ताज जीता

मनिका बत्रा ने लिली झांग को हराकर
ITTF विश्व कप में बनाई नॉकआउट की उम्मीद

तीन बार की ओलंपियन मनिका बत्रा ने मंगलवार को ।ITTF टेबल टेनिस विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से ध्यान खींचा। 30 साल की बत्रा ने ग्रुप 4 के मैच में अमेरिका की लिली झांग को 3-2 से मात दी और नॉकआउट राउंड की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत की। मुकाबला 43 मिनट तक चला और बत्रा ने सेटों में 11-7, 11-2, 14-16, 5-11, 11-6 का स्कोर दर्ज किया।बत्रा ने पहले मैच में जापान की मिवा हारिमोटो से हार का सामना किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए जीत का मनोबल बनाया। उनके ग्रुप 2 के पहले मैच में दुनिया की 43वें नंबर की खिलाड़ी श्रीजा अकुला को पुर्तगाल की फू यू ने 1-3 (11-8, 9-11, 13-15, 8-11) से हराया था।मनिका अब बुधवार को चीन की दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी वांग मान्यु से भिड़ेंगी। यह मुकाबला उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन बत्रा की हाल की जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।पुरुष वर्ग में भारतीय खिलाड़ी मानव ठक्कर को अपने पहले मैच में कोरिया के पार्क गंगह्योन से 0-3 की हार का सामना करना पड़ा। अब उन्हें ग्रुप 2 में स्वीडन के ओलंपिक रजत पदक विजेता ट्रूल्स मोरेगार्ड के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, ताकि नॉकआउट राउंड में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें।मनिका और मानव की ये कोशिशें भारतीय टेबल टेनिस के लिए बड़ी उम्मीद जगाती हैं। मनिका की अनुभव और संयमित खेल शैली उन्हें चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंदियों के खिलाफ फायदा दे सकती है। वहीं, मानव ठक्कर के लिए यह टूर्नामेंट सीखने और प्रदर्शन सुधारने का अवसर साबित होगा। टीम इंडिया की निगाहें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं, और देशवासियों को उम्मीद है कि वे अपनी कड़ी मेहनत और अनुभव से अच्छे परिणाम हासिल करेंगे।

शुभमन गिल ने धीमी पारी और
पिच को हार की वजह बताया

आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स की शुरुआत उतनी प्रभावशाली नहीं रही और मंगलवार रात पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मेहमान टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही, शीर्ष और मध्यक्रम में कोई भी खिलाड़ी बड़े स्कोर नहीं कर पाया और टीम केवल 163 रन पर ऑल आउट हुई। इस वजह से गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ गया, लेकिन आक्रामक गेंदबाजी के बावजूद जीत हाथ नहीं लगी।गुजरात ने अपने इम्पैक्ट प्लेयर प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी के लिए उतारा, जिन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। कृष्णा ने चार ओवरों में केवल 29 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट लिए और मैच को अंत तक खींचा। कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा कि टीम ने कई विकल्पों पर विचार किया और हालिया फॉर्म को देखते हुए सही समय पर कृष्णा को उतारा गया। गिल ने बताया कि कृष्णा ने टीम को 17वें और 18वें ओवर तक मैच में बनाए रखा। पंजाब किंग्स की ओर से आखिरी ओवरों में जोरदार प्रयास और तनावपूर्ण क्षणों के बावजूद गुजरात जीत नहीं पाई और तीन विकेट से मैच गंवा दिया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और कागीसो रबाडा को ओवर पूरा नहीं करने पड़ा, जबकि पिच धीमी होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े स्कोर बनाने में कठिनाई हुई। शुभमन गिल ने अपनी धीमी पारी को हार का मुख्य कारण बताया और कहा कि पिच की स्थिति और गेंद की पुरानी सतह के कारण रन बनाना आसान नहीं था।इस हार के बाद गुजरात को अपनी रणनीति और बल्लेबाजी लाइनअप पर गंभीरता से विचार करना होगा। कृष्णा की प्रभावशाली गेंदबाजी ने टीम को मुश्किल स्थिति में बनाए रखा, लेकिन बल्लेबाजी का कमजोर प्रदर्शन टीम की जीत की उम्मीदों को झटका पहुंचा गया।

महिला वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा
रन चेज अब न्यूजीलैंड के नाम

अमेलिया केर की शानदार कप्तानी में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में कीवी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 346 रन बनाए। कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने 74 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 69 रन बनाए, जबकि ऐनी बॉश ने 90 गेंदों में 91 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा सूने लूस ने 40 रन और विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा ने 37 रन का योगदान दिया। क्लो ट्राईऑन ने नाबाद 52 रन बनाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। कीवी गेंदबाजों में ब्रियरने इलिंग ने 3 विकेट लिए, जबकि केले नाइट और जेस केर ने क्रमशः दो-एक विकेट झटके। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने 347 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार वापसी की। कप्तान अमेलिया केर ने 139 गेंदों पर 23 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 179 रन की पारी खेली। उनके नेतृत्व और आक्रमक प्रदर्शन के दम पर टीम ने 8 विकेट खोकर 350 रन बनाकर लक्ष्य को केवल दो गेंद पहले हासिल कर लिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।इस दौरान भारतीय महिला टीम के रिकॉर्ड को भी चुनौती मिली। इससे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में 339 रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया था। अब न्यूजीलैंड ने 346 रन का पीछा करते हुए 350 रन बनाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया।इस ऐतिहासिक जीत ने न्यूजीलैंड महिला टीम के आत्मविश्वास को और बढ़ाया है। टीम के खिलाड़ियों ने आक्रामक बल्लेबाजी और सामूहिक प्रयास से यह साबित किया कि वे उच्च दबाव में भी शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं।

भेजा लव लेटर, शादी तक सोच डाली

84 साल की दादी को AI लड़के से प्यार

झांग युलान रोजाना 10 घंटे तक मोबाइल पर इन AI वीडियो को देखती थीं. धीरे-धीरे उन्हें लगने लगा कि उनका जियांगुओ के साथ सच्चा रिश्ता है. उन्होंने उसे मैसेज भेजे. इसके साथ ही हाथ से लिखकर प्रेम पत्र भी भेजा और यहां तक कि शादी के बारे में भी सोचा.

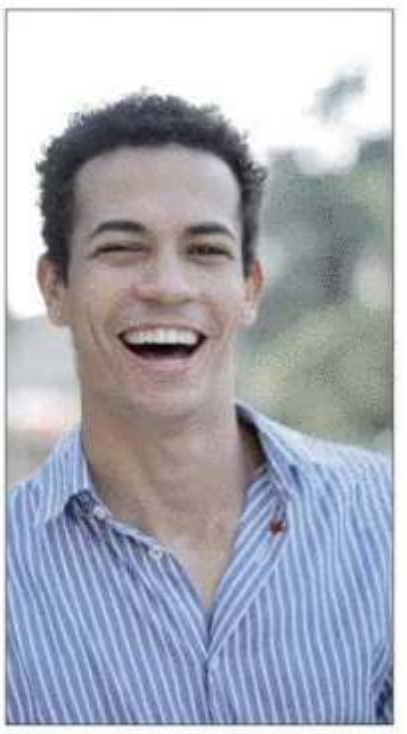

इस घटना पर लोगों ने सोशल मीडिया पर चिंता जताई. (Photo: Pexels)

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. यह तकनीक कई कामों को आसान बना रही है- जैसे ऑनलाइन मदद, चैटिंग, वीडियो बनाना और जानकारी देना.

लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जो हैरान करने वाले और थोड़े चिंताजनक हैं. ऐसा ही एक मामला चाईना से सामने आया है, जहां 84 साल की एक बुजुर्ग महिला एक AI से बनाए गए वर्चुअल इंसान के प्यार में पड़ गईं. यह इंसान असल में कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था, बल्कि कंप्यूटर से बनाया गया एक कैरेक्टर था. यह घटना दिखाती है कि AI सिर्फ एक तकनीक नहीं रह गई है, बल्कि यह लोगों की भावनाओं को भी प्रभावित कर सकती है. खासकर उन लोगों को, जो अकेलापन महसूस करते हैं या जिन्हें साथ और ध्यान की जरूरत होती है. यह कहानी Zhang Yu-lan नाम की महिला की है, जो चीन के हुबेई प्रांत में रहती हैं. उन्हें एक वर्चुअल यानी कंप्यूटर से बनाए गए इंसान से प्यार हो गया, जिसका नाम जियांगुओ था. यह कोई असली इंसान नहीं था, बल्कि AI द्वारा बनाया गया एक कैरेक्टर था, जिसे Bossy President कहा जाता है. चीन में 'बा जोंग' नाम का एक कैरेक्टर काफी लोकप्रिय है. यह ऐसा पुरुष किरदार होता है जो थोड़ा सख्त और कंट्रोल करने वाला होता है. लेकिन अपने पार्टनर के लिए बहुत केयरिंग और प्यार करने वाला होता है. ⊙

एआई से पकड़ में आई 25 साल पुरानी बीमारी

सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प मेडिकल स्टोरी तेजी से चर्चा में है, जिसमें एक परिवार ने दावा किया कि AI के साथ हुई एक बातचीत ने 25 साल पुरानी अनसुलझी मेडिकल समस्या की असली वजह तक पहुंचने में मदद की. यह पोस्ट रेडिट के r/ ClaudeAI कम्युनिटी में शेयर की गई. पोस्ट लिखने वाले शख्स ने बताया कि उनके 62 साल के चाचा, जो भारत में रहते हैं. ⊙

सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल

चीन में बीमार होने पर सड़क पर दवाइयां क्यों फेंकते हैं?

चीन में एक ऐसी परंपरा देखने को मिलती है, जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है. कई जगहों पर लोग पारंपरिक चीनी दवाइयों (जड़ी-बूटियों) के बचे हुए हिस्से को सड़क पर फेंक देते हैं. यह कोई गलती या कचरा फैलाने की आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक खास मान्यता और पुरानी कहानी जुड़ी हुई है. SCMP वेबसाइट के अनुसार, चीन में पारंपरिक दवाइयों (जिसे TCM यानी Traditional Chinese Medicine कहा जाता है) को लोग घर पर पकाते हैं. जब दवा तैयार हो जाती है, तो जो जड़ी-बूटियां बच जाती हैं, उन्हें कुछ लोग सड़क पर फेंक देते हैं. उनका

मानना होता है कि अगर लोग या गाड़ियां उस पर से गुजरेंगी तो बीमारी दूर हो सकती है. यह सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन यह एक पुरानी मान्यता है, जिसे कुछ लोग आज भी मानते हैं. इस परंपरा की जड़ें पुरानी लोककथा से जुड़ी मानी जाती हैं. ⊙

ऑस्ट्रेलिया में दिखा डरावना मंजर

खून जैसा लाल हुआ आसमान!

ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 28 मार्च को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. दिन के समय अचानक आसमान गहरे लाल रंग में बदल गया. शार्क बे और डेनहम जैसे इलाकों में चारों तरफ लाल धूल की चादर छा गई, जिससे सड़कें, घर और समुद्र का किनारा तक लाल नजर आने लगा. इस अजीब और डरावने नजारे के पीछे वजह बना ट्रॉपिकल साइक्लोन नरेल. ABC न्यूज के मुताबिक, तेज हवाओं ने रेगिस्तानी इलाके की आयरन-रिच लाल मिट्टी को हवा में उड़ा दिया. जैसे ही यह धूल आसमान में फैली, सूरज की रोशनी उसके बीच से गुजरते हुए स्कैटर हुई और पूरा आसमान खून

तेज हवाओं ने रेगिस्तानी इलाके की आयरन-रिच लाल मिट्टी को हवा में उड़ा दिया.

जैसा लाल दिखने लगा. 27 मार्च को साइक्लोन नरेल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ-वेस्ट कोस्ट पर पहुंचा. हवाओं की रफ्तार 250 किमी/घंटा तक दर्ज की गई. तेज हवाओं के चलते विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई और लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए. स्थानीय लोगों ने इस मंजर को "इनक्रेडिबली ईरी" और "अपोकैलिप्टिक" बताया. शार्क बे कैरावन पार्क ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाहर का माहौल बेहद अजीब और डरावना है, हर चीज धूल से ढकी हुई है. साइक्लोन का सबसे ज्यादा असर एक्समाउथ शहर में देखा गया. एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा.हजारों घरों की बिजली चली गई. ⊙

मंच पर बुलाया, लेकिन बोलने नहीं दिया

मुंबई समारोह में सुनील पाल के साथ हुआ अपमान

मुंबई में हाल ही में आयोजित एक सम्मान समारोह में कॉमेडियन सुनील पाल के साथ हुई घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। समारोह का उद्देश्य उनका सम्मान करना था, लेकिन जो कुछ हुआ वह किसी के लिए भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। कार्यक्रम के दौरान पाल को मंच पर बुलाया गया और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया, जिससे यह प्रतीत हुआ कि उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जा रहा है।लेकिन जैसे ही सुनील पाल कुछ शब्द बोलने के लिए आगे बढ़े, आयोजकों ने उन्हें माइक देने से इनकार कर दिया और उन्हें अपनी सीट पर वापस जाने को कहा। घटना के वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पाल स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं और विनम्रता से मंच पर बोलने का अवसर मांग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने

आयोजकों से कहा, "कम से कम मुझे धन्यवाद तो कहने दीजिए," लेकिन आयोजक बार-बार उन्हें लौट जाने का संकेत करते रहे और उन्हें दर्शकों के सामने बोलने का मौका नहीं दिया।सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है और यूजर्स ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। कई लोगों ने इसे असभ्यता और अनुचित व्यवहार बताया। एक यूजर ने लिखा, "यह बहुत ही असभ्य है।" दूसरे ने कहा, "या तो बुलाओ मत, बुलाया है तो इज्जत करो। चाहे व्यक्ति कोई भी हो।" तीसरे ने लिखा, "उन्हें बोलने न देना वाकई बहुत बड़ा अपमान था।" इस मामले ने कलाकारों के सम्मान को लेकर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है।सोशल मीडिया पर सुनील पाल के समर्थन में भी कई प्रतिक्रियाएँ आई हैं। लोग उन्हें न्याय और सम्मान का हकदार मानते हुए आयोजकों के इस व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा कि कलाकारों के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है और हर व्यक्ति को अपने प्रयासों और योगदान के लिए सम्मान मिलना चाहिए। कुछ ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएँ समाज में गलत संदेश देती हैं और सार्वजनिक मंचों पर सम्मान की परंपरा को कमजोर करती हैं।जहाँ तक आयोजकों का सवाल है, उन्होंने अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। कुछ सूत्रों का मानना है कि यह निर्णय सुनील पाल के पहले किए गए विवादित बयानों से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना ने न केवल आयोजकों की आलोचना को जन्म दिया है, बल्कि कॉमेडियन और कलाकारों के प्रति सम्मान की आवश्यकता पर भी सवाल खड़ा किया है। कुल मिलाकर, मुंबई समारोह में सुनील पाल के साथ हुई यह घटना सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा का विषय बन गई है। वीडियो में दिखाई गई असमंजसपूर्ण और अपमानजनक स्थिति ने दर्शकों और यूजर्स दोनों को हैरान कर दिया। अब सबकी नजर आयोजकों पर है कि वे इस विवाद पर अपना पक्ष कब और कैसे सामने लाते हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कलाकारों के सम्मान और मंच पर उचित व्यवहार को लेकर समाज की संवेदनशीलता बढ़ी है और ऐसे मामलों में त्वरित स्पष्टता और माफी की उम्मीद की जाती है।

सवर्ण मोर्चा ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर प्रदर्शन किया

लखनऊ में सवर्ण मोर्चा ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर शंख बजाकर प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम ने प्रदर्शनकारियों से संवाद कर आश्वासन दिया कि किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। विरोध शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

सवर्ण मोर्चा ने बुधवार को यूजीसी के नए नियमों के विरोध में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शंख बजाकर विरोध जताया और नए नियमों को "काला कानून" बताते हुए नारेबाजी की। इस दौरान करीब 50 से अधिक लोग उपस्थित थे। प्रदर्शन के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हाथ जोड़े हुए प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे। कमर तक झुककर उन्होंने अभिवादन किया, जिसे देखकर प्रदर्शनकारी भी प्रणाम में लौटे। इसके बाद डिप्टी सीएम ने स्वयं कमरे का दरवाजा खोला और सभी को अंदर बुलाकर बातचीत की। सवर्ण मोर्चा के पदाधिकारियों ने डिप्टी सीएम से पूछा कि यूजीसी के नए नियम क्यों लागू किए जा रहे हैं और इसके तहत सवर्ण छात्रों के साथ अन्याय की आशंका क्यों बनी है। इस पर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं सामान्य वर्ग से आते हैं और अपने वर्ग के किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार सभी धर्म और जाति के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करती है। मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह, प्रवक्ता पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी और बसंत सिंह बघेल ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम को बताया कि नए नियम सवर्ण समाज के छात्रों के हितों के खिलाफ हैं। संदीप सिंह ने कहा, "उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सवर्ण समाज को कमजोर करने के लिए यह नियम लाए जा रहे हैं। यह काला कानून किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई फर्जी मुकदमा दर्ज कर देगा तो सवर्ण छात्र का जीवन बर्बाद हो सकता है। यही कारण है कि हम पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं और जब तक यह कानून पूरी तरह से वापस नहीं होगा, विरोध जारी रहेगा।"संदीप सिंह ने आगे कहा कि दलित एक्ट पहले से ही लागू था, लेकिन यूजीसी के नए नियम क्यों लाए गए, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी छात्र के खिलाफ झूठा मामला दर्ज हुआ तो उसकी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बातचीत के दौरान आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को दिल्ली नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा और किसी भी कीमत पर सवर्ण समाज के छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार सभी धर्म और जाति के साथ है। हम स्वयं सामान्य वर्ग से आते हैं, इसलिए अपने वर्ग के किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।" बातचीत के बाद प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध समाप्त किया। मोर्चा के पदाधिकारी यह भी कह रहे हैं कि यदि इस कानून को लेकर सरकार से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो भविष्य में व्यापक आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। इस घटना ने लखनऊ में यूजीसी नियमों को लेकर चल रहे विवाद को और तेज कर दिया है। सवर्ण मोर्चा का कहना है कि वे अपने अधिकारों के लिए हर स्तर पर आवाज उठाते रहेंगे और सरकार से स्पष्ट जवाबदेही की मांग करेंगे।

CBI ने एलआईसी घोटाले का फरार आरोपी समीर जोशी लखनऊ से किया गिरफ्तार

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने एलआईसी में करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 11 साल पुराने इस मामले में फरार चल रहे अपराधी समीर जोशी को लखनऊ के एक मेट्रो स्टेशन से दबोचा गया। अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है। CBI ने यह मामला 13 अगस्त 2012 को एलआईसी, लखनऊ की शिकायत पर दर्ज किया था। आरोप था कि फरवरी 2006 से अगस्त 2010 के बीच जानकीपुरम स्थित एलआईसी कार्यालय में फर्जी चेक तैयार कर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने गैर-मौजूद पॉलिसी धारकों के नाम पर फर्जी क्लेम दिखाकर एलआईसी फंड से 6.37 करोड़ रुपए निकाल लिए। इस घोटाले को छिपाने के लिए खातों में हेरफेर और फर्जी एंट्री भी की गई। CBI ने जांच पूरी होने के बाद 21 अगस्त 2014 को 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें समीर जोशी का नाम भी शामिल था। जांच के दौरान सामने आया कि समीर जोशी ने एलआईसी के तत्कालीन हायर ग्रेड असिस्टेंट पंकज सक्सेना के साथ मिलकर साजिश रची। दोनों ने मिलकर समीर जोशी, उनकी पत्नी अंजू जोशी और कर्मचारी जितेंद्र कुमार के नाम पर फर्जी चेक तैयार किए। CBI के अनुसार, फर्जी चेक के जरिए करीब 62 लाख रुपए की राशि निकाली गई, जिसे आरोपियों ने आपस में बांट लिया। समीर जोशी को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। इसके बाद वह फरार हो गया और लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा।

मोहनलालगंज में स्लीपर बस घर में घुसी चालक और कंडक्टर घायल

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

मोहनलालगंज क्षेत्र के फूलवरिया मोड़ के पास मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे एक स्लीपर बस बेकाबू होकर घर में जा घुसी। बस वाराणसी से प्रयागराज होते हुए जयपुर जा रही थी। हादसे के समय बस में लगभग 30-35 यात्री सवार थे, जिनमें चीख-पुकार मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ज्योति नगर की ओर से अचानक सामने आए एक ट्रक को बचाने के प्रयास में बस चालक ने वाहन को दाहिनी ओर मोड़ा। इस कारण बस अनियंत्रित हो गई और सीधे इस्लाम मोहम्मद के मकान में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि मकान का मुख्य गेट और दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घर के सदस्य मेन गेट से हटकर पीछे वाले कमरे में सो रहे थे, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।हादसे में बस चालक विवेक चौहान (42), निवासी कोतवाली इटावा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में फ्रैक्चर आया है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीएचसी मोहनलालगंज से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बस परिचालक हर्षदीप (25), निवासी गंगानगर, राजस्थान भी घायल हुए और उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया।बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आईं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें अन्य वाहनों से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया।घटना की सूचना मिलते ही मोहनलालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने क्रेन की मदद से

क्षतिग्रस्त बस को सड़क से हटवाया, जिससे कुछ समय के लिए बाधित यातायात जल्द ही सामान्य हो गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण अचानक सामने आए ट्रक को बचाने के प्रयास में बस का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर चालक सतर्क नहीं होते और घर में कोई सदस्य मेन गेट के पास होता, तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था। इस घटना ने क्षेत्रवासियों में सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ा दी है।

नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के बाद हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लोकगायिका नेहा सिंह राठौर ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के बाद हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पूरी की। यह कदम पहलगाम आतंकी हमले और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी से जुड़े मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए उठाया गया। उनके साथ पति हिमांशु सिंह भी मौजूद थे। हिमांशु ने बताया कि थाने में SHO के मौजूद न होने के कारण बेल प्रक्रिया तुरंत पूरी नहीं हो सकी, जिससे उन्हें कुछ समय इंतजार करना पड़ा। नेहा सिंह राठौर को 10 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने यह मानते हुए उन्हें राहत दी कि गायिका पहले ही जांच एजेंसियों के सामने पेश हो चुकी हैं और अपना बयान दर्ज करा चुकी हैं। शीर्ष अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया और निर्देश दिया कि वे जांच में पूरी तरह सहयोग करें। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 7 जनवरी को उन्हें अंतरिम राहत मिली, जबकि 10 मार्च को उन्हें स्थायी अग्रिम जमानत प्रदान की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नेहा सिंह राठौर को जांच में लगातार सहयोग करना होगा। फिलहाल, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।इस कदम से गायिका की कानूनी स्थिति थोड़ी स्पष्ट हुई है, लेकिन मामले की गहन जांच और कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है।

माई जी का पुरवा गांव में रातभर लूट, 5 साल की बच्ची को उठा ले गए बदमाश

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के माई जी का पुरवा गांव में देर रात बदमाशों ने दो घरों में लाखों रुपये के गहने और अन्य कीमती सामान पार कर दिया। इस दौरान परिवार को बंधक बनाया गया और विरोध करने पर महिला के सिर पर कट्टा तान दिया गया।ग्रामीणों के अनुसार, बदमाशों ने राजपाल रावत और आशीष यादव के घरों को निशाना बनाते हुए छत के रास्ते अंदर घुसकर चोरी की। दोनों घरों में नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान पार किया गया। पीड़ित आशीष यादव की पत्नी नीतू ने बताया कि रात में चार बदमाश घर में घुसे थे। उन्होंने पहले घर के दरवाजे बंद किए और फिर तीन बदमाश कमरे में दाखिल हुए।बदमाश अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे गहने निकालने लगे। परिवार जागा तो एक बदमाश ने कट्टा तानकर सभी को चुप रहने की धमकी दी। पूरा सामान समेटने के बाद जब बदमाश भागने लगे, तो उनकी पांच साल की बेटी काव्या को भी उठा ले गए। ग्रामीणों के शोर मचाने और पीछा करने पर बदमाश बच्ची को कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में सघन निगरानी और खोजबीन की जा रही है।

ऐशबाग डबल मर्डर केस में 19 साल बाद बड़ा फैसला, विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोपित बरी

राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में 19 साल पुराने चर्चित डबल मर्डर केस में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में गोसाईंगंज (अयोध्या) के विधायक अभय सिंह समेत सभी चार आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में रविंद्र उर्फ रज्जू, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही और फिरोज अहमद भी आरोपी थे, जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया।31 मार्च 2007 की रात यह घटना हुई थी, जब ऐशबाग ईदगाह के सामने बाइक सवार बदमाशों ने पूर्वांचल टेंट हाउस के मालिक शत्रुघ्न सिंह उर्फ छोटू और उनके नौकर जितेंद्र त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच के दौरान इस हत्याकांड में विधायक अभय सिंह की कथित संलिप्तता सामने आई थी। उस समय अभय सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत लखनऊ जिला जेल में बंद थे। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर 13 अगस्त 2008 को चार्जशीट दाखिल की थी।सुनवाई के दौरान कई अहम पहलुओं ने अभियोजन पक्ष की स्थिति कमजोर कर दी। पुलिस हत्या में इस्तेमाल असलहा बरामद करने में असफल रही। इसके अलावा, पंचायतनामा में शामिल गवाहों ने ट्रायल के दौरान विरोधाभासी बयान दिए, जिससे केस और कमजोर हुआ। कोर्ट ने यह भी माना कि घटना के समय अभय सिंह जेल में बंद थे, जो उनके पक्ष में गया। करीब 19 साल तक चले इस मुकदमे में आखिरकार सभी आरोपित बरी कर दिए गए। लंबे समय बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर पुराने मामलों में साक्ष्यों और जांच की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे मामलों में साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान को मजबूती से सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले का लंबा खिंचाव और आरोपितों की बरी होने की प्रक्रिया न्याय व्यवस्था की धीमी गति को उजागर करती है। वहीं, पीड़ित परिवार के लिए यह फैसला भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण है। परिवार ने कहा कि उन्हें न्याय मिलने में इतने साल लग गए, जिससे उनके मनोबल और भरोसे पर असर पड़ा। यह घटना इस बात का उदाहरण भी है कि

लंबे समय तक लंबित मामलों में सबूतों का कमजोर होना, गवाहों की अनुपस्थिति या विरोधाभासी बयान, और जांच की गुणवत्ता न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इस फैसले ने पुराने मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

उन्नाव: लाखों की होम्योपैथी दवाएं कूड़े में

सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में जिला होम्योपैथी चिकित्सालय परिसर से लाखों रुपये मूल्य की होम्योपैथी दवाएं कूड़े के ढेर में मिलने की घटना ने स्वास्थ्य विभाग और दवा प्रबंधन प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अस्पताल परिसर के एक हिस्से में बड़ी संख्या में दवाओं के डिब्बे खुले में फेंके गए पाए गए। आरोप है कि यह दवाएं मरीजों के इलाज के लिए विभिन्न केंद्रों पर भेजी जानी थीं, लेकिन उन्हें "एक्सपायरी" या "खराब" बताकर छंटाई के नाम पर फेंक दिया गया। इस मामले से वित्तीय अनियमितता और विभागीय लापरवाही की आशंका भी बढ़ गई है।यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब सरकारी अस्पतालों में अक्सर दवाओं की कमी की शिकायतें आती रहती हैं और मरीजों को मजबूरी में बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में लाखों रुपये की दवाओं का खुले में मिलना अनेक सवाल खड़े करता है। कुछ चिकित्सकों ने, नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें अक्सर पर्याप्त दवाएं नहीं मिलतीं, जिससे मरीज बिना इलाज लौटने को मजबूर होते हैं।जिला होम्योपैथी अधिकारी डॉ. रश्मि सिंह ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि बारिश में भीगने और एक्सपायरी की आशंका के कारण दवाओं को अस्थायी रूप से बाहर रखा गया था। डॉ. सिंह के अनुसार, इन दवाओं को बाद में सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना था। उन्होंने यह भी बताया कि यह खेप केरल से प्राप्त हुई थी और वर्ष 2024 की एक्सपायरी से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है।हालांकि, विभाग के इस स्पष्टीकरण के बावजूद कई सवाल अनुत्तरित हैं। यदि दवाएं खराब थीं, तो उनका नियमानुसार निस्तारण क्यों नहीं किया गया और उन्हें खुले में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सूत्रों के मुताबिक, कुर्सट और लालऊखेड़ा सहित अन्य केंद्रों पर इसी खेप की दवाएं मरीजों को दिए जाने की भी जानकारी मिली है, जिससे स्थिति और जटिल बनती है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं, बल्कि मरीजों के भरोसे और विभागीय जवाबदेही पर भी गंभीर असर डालती हैं। उनका मानना है कि दवाओं के सही और सुरक्षित प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियमों का पालन अनिवार्य है। स्थानीय लोगों और मरीजों में भी नाराजगी देखने को मिली है। उनका कहना है कि यदि अस्पताल में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध नहीं हैं और दवाएं खुले में फेंकी जा रही हैं, तो यह आम जनता के साथ अन्याय है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि वह इस मामले की पूरी जांच कर दोषियों को जवाबदेह ठहराए और भविष्य में ऐसी लापरवाहियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में दवा प्रबंधन की कमियों और निगरानी प्रणाली की कमजोरी को उजागर किया है, जिससे मरीजों की सुरक्षा और इलाज की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।

उन्नाव से शुक्लागंज तक चली 16 एंबुलेंसों की अनोखी अंतिम यात्रा

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई ने अपने दिवंगत भाई की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी अंतिम यात्रा में 16 एंबुलेंस शामिल कर दीं। एक साथ सायरन बजाती एंबुलेंसों का यह काफिला जब सड़कों से गुजरा, तो हर कोई हैरान रह गया। जब लोगों को इसकी असल वजह पता चली, तो उनकी आंखें नम हो गईं। यह घटना उन्नाव के पूरन नगर मोहल्ले की है। यहां के निवासी कमलेश, जो पेशे से राजमिस्त्री थे, लंबे समय से लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। जब भी उनकी तबीयत बिगड़ती, उनके भाई विमलेश जो पेशे से एंबुलेंस चालक हैं उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाते और वापस घर लाते थे। यह सिलसिला कई वर्षों से चलता आ रहा था। विमलेश के मुताबिक, कमलेश की एंबुलेंस से एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव बन गया था। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई थी कि जब उनकी मृत्यु हो, तो उनकी अंतिम यात्रा एंबुलेंसों के साथ निकले। शनिवार को कमलेश का निधन हो गया। रविवार को उनकी अंतिम यात्रा निकाली जानी थी। ऐसे में विमलेश ने अपने अन्य एंबुलेंस चालक साथियों को संपर्क कर उन्हें एंबुलेंस के साथ घर बुलाया। इसके बाद कुल 16 एंबुलेंसों के साथ कमलेश की अंतिम यात्रा निकाली गई, जो उन्नाव से शुक्लागंज श्मशान घाट तक पहुंची। जब एक साथ सायरन बजाती हुई एंबुलेंसों का काफिला सड़कों पर निकला, तो लोग चौंक गए। कई लोगों को लगा कि कोई बड़ी आपात स्थिति हो गई है। हालांकि, जब उन्हें इस घटना की सच्चाई पता चली, तो हर कोई भावुक हो गया। यह दृश्य देखने और सुनने वाले लोगों की आंखें नम हो गईं।

सदर कोतवाली में साइबर ठगी का मामला, बुजुर्ग महिला से 33 हजार रुपये ठगे गए

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

सदर कोतवाली क्षेत्र में एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला को साइबर ठगी का सामना करना पड़ा, जिसमें ठग ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर महिला को डराया और अश्लील वीडियो के नाम पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर 33 हजार रुपये ठग लिए। मामला तब उजागर हुआ जब परिवार को घटना की जानकारी मिली और तुरंत बैंक खाते को फ्रीज कराया गया।घटना तीन अगस्त 2024 की दोपहर साढ़े बजे की है, जब महिला के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को गोमतीनगर थाने में तैनात सीओ रैंक के अधिकारी के रूप में पेश किया। ठग ने महिला को डराते हुए कहा कि वह अश्लील वीडियो देखती हैं और इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जेल जाने से बचने के लिए उन्हें तुरंत गूगल पे के माध्यम से पैसे भेजने को कहा गया। भयभीत महिला ने झांसे में आकर पहले 7,550 रुपये और फिर 28,550 रुपये ट्रांसफर किए। कुल मिलाकर ठग ने 33 हजार रुपये ठग लिए। इसके बावजूद आरोपी ने और पैसे की मांग करना शुरू कर दिया। तभी महिला के परिजनों को घटना की जानकारी मिली। परिवार ने तत्काल एसपी कार्यालय का रुख किया और आरोपी नंबर पर सर्विलांस लगाने की मांग की।पुलिस की तत्परता से जिस बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की गई थी, उसे तुरंत फ्रीज कर दिया गया। इसके साथ ही पीड़िता ने ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई। न्यायालय में धनराशि रिलीज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनवाई भी पूरी की गई। अदालत ने धनराशि रिलीज करने से पहले संबंधित थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए।पीड़िता ने सदर कोतवाली में तहरीर दी, जिसके आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है और बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से मामले की जांच भी कर रही है। यह घटना साइबर अपराध की गंभीरता को उजागर करती है और यह दिखाती है कि कैसे ठग बुजुर्ग और अनुभवहीन लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बना सकते हैं। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा कि किसी भी अज्ञात कॉल या संदेश पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

उन्नाव के नवाबगंज में सीएनजी ऑटो चालकों ने अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन किया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

सीएनजी ऑटो चालकों ने अवैध वसूली और मनमानी शुल्क के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चालकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।प्रदर्शन में शामिल चालकों का आरोप है कि नगर पंचायत बिना किसी स्पष्ट नियम के उनसे प्रतिदिन 20 से 30 रुपये जबरन वसूल रही है। चालकों का कहना है कि इस वसूली का कोई लिखित आदेश या नियम उन्हें नहीं दिखाया जाता, फिर भी भुगतान का दबाव बनाया जाता है। पैसे न देने पर उन्हें विभिन्न स्थानों पर रोककर परेशान किया जाता है और वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाती।चालकों ने बताया कि नवाबगंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में सीएनजी ऑटो चालक अपने परिवार का भरण-पोषण ऑटो चलाकर करते हैं। नगर पंचायत के अवैध शुल्क ने उनकी आजीविका को प्रभावित किया है और उन्हें आर्थिक तथा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चालकों का कहना है कि अधिकृत ऑटो स्टैंड केवल कुछ सीमित स्थानों पर हैं, जबकि नगर पंचायत पूरे क्षेत्र में वसूली कर रही है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुविधाएं और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार संचालन का अवसर नहीं दिया जा रहा।यह ज्ञापन सीएनजी ऑटो यूनियन उन्नाव के अध्यक्ष गोपाल महेश्वरी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को सौंपा गया। मौके पर बड़ी संख्या में ऑटो चालक और यूनियन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ज्ञापन में प्रशासन से आग्रह किया गया कि अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषी अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।यूनियन अध्यक्ष गोपाल महेश्वरी ने कहा, "ऑटो चालक पहले से ही महंगाई और कम आमदनी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में जबरन वसूली उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन गई है। यदि प्रशासन जल्द समाधान नहीं करता है, तो चालक आंदोलन करने को मजबूर होंगे।"स्थानीय लोग भी चालकों के समर्थन में खड़े हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सभी नियमों के पालन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। चालकों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अपने हक की रक्षा करना है और वे किसी भी तरह की मनमानी वसूली बर्दाश्त नहीं करेंगे।इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय ने फिलहाल ज्ञापन प्राप्त करने की पुष्टि की है और कहा है कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी वसूली गतिविधियों को नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ ही संचालित किया जाना चाहिए।

उन्नाव में मौसम बदला, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में मंगलवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। मौसम बदलना देर रात शुरू हुआ, जब अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में घने बादल छा गए। इसके बाद जिले के कई ग्रामीण और शहरी इलाकों में बारिश हुई। बारिश के चलते न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। शहर क्षेत्र में बारिश से सड़कों पर ठंडक महसूस की गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तेज हवा और बारिश का असर ज्यादा देखने को मिला। कई जगह पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गईं, जबकि कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी थोड़ी देर के लिए बाधित रही। हालांकि, मौसम का यह बदलाव किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इस समय जिले में गेहूं की कटाई का कार्य अंतिम चरण में है और बड़ी मात्रा में फसल खेतों में कटी पड़ी है। अचानक हुई बारिश से गेहूं भीग गया, जिससे दानों की गुणवत्ता प्रभावित होने और उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि अगर मौसम इसी तरह बना रहा तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने फसल की मड़ाई की तैयारी कर ली थी, लेकिन बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में पानी भर जाने से फसल सूखने में समय लगेगा, जिससे बाजार में बिक्री भी प्रभावित हो सकती है।

गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर 80 साल पुराने पीपल के पेड़ को हटाने का काम शुरू, स्थानीय लोग नाराज़

गंगाघाट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार परियोजना के तहत लगभग 80 वर्ष पुराने पीपल के पेड़ को काटने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान तकनीकी दिक्कतें और एक युवक के घायल होने की घटना ने स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी और चर्चा का माहौल बना दिया।रेलवे विभाग के अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। परियोजना के तहत प्लेटफॉर्म के पास स्थित पुराने पीपल को हटाना आवश्यक हो गया क्योंकि इसकी शाखाएं ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) लाइन के बेहद करीब पहुंच चुकी थीं। तेज हवा या बारिश के दौरान शाखाओं के गिरने से रेल संचालन बाधित होने और दुर्घटना की आशंका थी। मजदूरों ने पेड़ काटने का कार्य शुरू किया, लेकिन कटर मशीन लगातार तीन बार खराब होने के कारण कार्य में बाधा आई। इसी दौरान पेड़ की एक बड़ी शाखा काटते समय आसिफ नामक एक युवक संतुलन खो बैठा और गिरते-गिरते बाल-बाल बचा। उसे मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उपचार दिया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए कार्य रोक दिया गया और मजदूरों को सुरक्षा निर्देश दिए गए।स्थानीय लोग इस पेड़ को दशकों पुरानी धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं। कई निवासी वर्षों से इस पीपल की पूजा करते आए हैं। पेड़ काटे जाने की सूचना मिलते ही लोग मौके पर पहुंचे और अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने रेलवे प्रशासन से पेड़ को बचाने या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा कारणों और यात्रियों की सुविधा के लिए पेड़ हटाना अनिवार्य था, लेकिन सभी कार्य सावधानीपूर्वक और नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की स्थिति का लिया जायजा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को फसलों के नुकसान का तुरंत आकलन करने, आंकड़े संकलित करने और समयबद्ध तरीके से मुआवजा वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार का उद्देश्य किसानों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना और जल्द राहत प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों से किसानों को हो रही दिक्कतों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रतिकूल मौसम के कारण किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए और उनका कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों की फसलों को हुए नुकसान का तुरंत आकलन किया जाए और संपूर्ण आंकड़े संकलित किए जाएँ। इसके बाद, प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कृषि प्रधान सचिव और राहत आयुक्त को भी निर्देश दिए कि वे जमीनी अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क बनाए रखें और राहत कार्यों में समन्वय सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी जानकारी समय पर एकत्रित कर सरकार को उपलब्ध कराई जाए, ताकि राहत कार्यों में कोई भी बाधा न आए।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जैसे ही फसलों के नुकसान का आकलन प्राप्त होता है, मुआवजे का वितरण तुरंत शुरू कर दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से समयबद्ध तरीके से पूरी की जानी चाहिए ताकि प्रतिकूल मौसम से प्रभावित किसान जल्द से जल्द राहत प्राप्त कर सकें।अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में किसानों से प्रत्यक्ष संवाद किया जाए और उनकी समस्याओं को सुनते हुए त्वरित समाधान निकाला जाए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी आय, फसलों और जीवनयापन को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर, कृषि विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रभावित जिलों में फसलों की स्थिति, नुकसान का प्रारंभिक आकलन और राहत वितरण की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर जिले में फसलों के नुकसान का सही आंकलन करने और प्रभावित किसानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह बैठक राज्य सरकार की किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की आमदनी और फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऐसे में सरकार की यह पहल प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने और उनके आर्थिक संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में किसानों को अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ प्रभावित किसानों को आवश्यक सरकारी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाए।इस समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि फसलों के नुकसान का आकलन और प्रभावित किसानों को राहत वितरण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इससे राज्य के किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी और उन्हें सरकार की ओर से समुचित सहायता प्राप्त होगी।

कार्ड दिखाओ, सिलिंडर पाओ: यूपी के इस जिले में शादी समारोह के लिए नई व्यवस्था लागू

एलपीजी की किल्लत के बीच शादी वाले परिवारों के लिए राहत की खबर है। बरेली जिले में शादी समारोह के लिए एलपीजी सिलिंडर आपूर्ति के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत आयोजक को शादी के कार्ड के साथ आवेदन करना होगा। इसके बाद उन्हें सिलिंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) संकट के बीच वैवाहिक आयोजनों की चिंता से निजात पाने के लिए बरेली जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्था लागू की है। आयोजकों को सिलिंडर के लिए जिलाधिकारी या पूर्ति कार्यालय में विवाह के कार्ड के साथ प्रार्थनापत्र देना होगा। कितने सिलिंडर दिए जाएंगे ये अफसर तय करेंगे। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से कच्चे तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित होने से एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हुई है।15 अप्रैल से सहालग शुरू हो रहे हैं। इधर आयोजकों को आतिथ्य के साथ ही केटरर्स और मैरिज हॉल संचालक को कारोबार की चिंता सता रही है।बताते हैं कि पूर्व में हुई बुकिंग निरस्त कराने के लिए आयोजक संपर्क करने लगे हैं, लेकिन कारोबारी सांत्वना दे रहे हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सिलिंडर वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी है, ताकि वैवाहिक आयोजनों को लेकर लोग निश्चिंत रहें। हालांकि, यह सिलिंडर सशर्त ही उपलब्ध होंगे आयोजन के बाद सभी खाली सिलिंडर एजेंसी को वापस करने होंगे। तब उनकी जमा की गई सिक्योरिटी मनी 2400 रूपये वापस कर दी जाएगी और अस्थायी कनेक्शन भी रद्द कर दिया जाएगा। अगर किन्हीं वजहों से आयोजक एक या दो सिलिंडर वापस नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं होगी। इसलिए आयोजकों से सहयोग की अपील की गई है।

IAS रिंकू सिंह राही का साफ जवाब: "मैंने इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ तकनीकी विकल्प मांगा है"

2021 बैच के IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही मंगलवार को अचानक सुर्खियों में आ गए, जब मीडिया में उनके इस्तीफे की खबरें सामने आईं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी है और जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, वे गलत हैं। 26 मार्च को उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर टेक्निकल रेजिगनेशन (तकनीकी विकल्प) का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, "इसे नौकरी छोड़ने की बात न समझा जाए, यह केवल एक विकल्प या अनुरोध है।"रिंकू सिंह राही का कहना है कि यदि उनसे वर्तमान पद पर काम नहीं लिया जा रहा है, तो उन्हें उनकी मूल सेवा (PCS) में वापस भेज दिया जाए। उन्होंने बताया कि वे IAS बनने से पहले PCS अधिकारी थे और अब मूल कैडर में लौटकर काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कुछ अधिकारी सरकारी सिस्टम को समझ नहीं पाते और नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन वे सेवा छोड़ना नहीं चाहते। सिस्टम में कुछ कमियां हैं, जिन्हें सुधारा जा सकता है। 44 वर्षीय रिंकू सिंह राही के पास अभी अपनी 16 साल की IAS सेवा शेष है। उन्हें लगभग 8 महीने पहले शाहजहांपुर से हटाकर राजस्व परिषद भेजा गया था। इसके बाद उन्हें किसी फील्ड पोस्टिंग में शामिल नहीं किया गया। वह पहले शाहजहांपुर के पुवायां तहसील में SDM के पद पर तैनात थे। इस दौरान वकीलों के सामने उठक-बैठक को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्हें वहां से हटा दिया गया। रिंकू सिंह राही का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल सरकारी सिस्टम में सुधार करना और सेवा में योगदान देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका तकनीकी विकल्प केवल उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास है, न कि नौकरी छोड़ने का इशाराइस बयान के बाद IAS रिंकू सिंह राही के भविष्य की पोस्टिंग और PCS कैडर में लौटने की संभावनाओं पर अब चर्चा तेज हो गई है।

हाथरस के विकास को लेकर सीमा उपाध्याय की सीएम योगी से मुलाकात, रखे अहम प्रस्ताव

हाथरस से जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा रामवीर उपाध्याय ने मंगलवार को लखनऊ पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान जनपद हाथरस के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा रामवीर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि हाथरस जनपद में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे और उनके शीघ्र स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला पंचायत पूरी तत्परता से कार्य कर रही है और आगे भी विकास कार्यों को गति देने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा हाथरस जनपद के विकास में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का भी आश्वासन दिया ताकि प्रस्तावित योजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष की इस पहल को जनपद के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी हाथरस